ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with a view to set up a satellite town near Joru Bungalow (Ghoom). the Chairman of Darjeeling Gorkha Hill Council has asked the permission of the Forest Department as the proposed land belong to that Department;

(b) if so, whether permission has been granted or is under consideration; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) References have been received from Chairman, Darjeeling Gorkha Hill Council asking for use of forest land for setting up of Satellite township near Joru Bungalow, However, formal proposal for diversion of forest land for this purpose has not been received under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(b) and (c) Do not arise.

Developmental Programmes on Tourism in Darjeeling

2844. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FOREST be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Darjeeling Gorkha Hill Council has asked the Central Government for permitting it to use forest land for taking up developmental programmes on tourism and other sectors;

(b) if so, what are the details of the proposals; and

(c) what is the response of Government on these proposals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Some references have been received from the Darjeeling Gorkha Hill Council for permitting it to use forest land for taking up developmental programmes in tourism and other sectors. However formal proposal for diversion of forest land for tourism and other related purposes in Darjeeling has not been received under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(b) and (c) Do not arise.

नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए योजना

2845. **श्री गोविन्दराव आदिक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए समय-समय पर योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए की भारी राशि खर्च करने के बावजूद प्रदूषण अपेक्षाकृत बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन योजनाओं की असफलता के क्या कारण हैं; और

(च) प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा आठ वर्ष पहले गंगा कार्य योजना का सबसे प्रदूषित भारतीय नदियों में एक प्रदूषित और सबसे लम्बी नदी के प्रदूषण निवारण की स्कीमें हाथ में लेने के लिए तैयार की गई थी। अब गंगा कार्य योजना का वह पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है, गंगा कार्य योजना का चरण-II, गंगा के कुछ नगरों के लिए साथ ही इसकी प्रमुख सहायक नदियों यमुना और गोमती के लिए हाथ में लिया गया है, इस अनुभव के आधार पर, सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है जो कि देश के 12 राज्यों में स्थित 17 नदियों के 22 अधिनिर्धारित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के संबंध में है।

गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत घरेलू सीवेज के दिशा परिवर्तन, अवशोधन एवं उसके उपचार की अल्प-लागत स्वच्छता, विद्युत/उन्नत लकड़ी आधारित शवदाहगृह नदी तटाग्र विकास तथा अन्य जैव स्कीमें, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के 25